Malpractices in Letters of Intent for Setting up Industries in Backward Areas

2377. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have seen press report to the effect that people do not set up an industry in backward areas even though they profess to do so and use the letters of intent for blocking the capacity; and

(b) if so, the steps the Central Government have taken to check such malpractices in regard to letters of intent issued by them?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) There have been press reports to the effect that letters of intent granted for setting up industrial capacities in backward areas are not implemented and that there has been blocking of capacity. Implementation of letters of intent are monitored by the administrative Ministries and validity of the letters of intent are extended by them only after satisfying that the parties have taken appropriate steps towards implementation of the letters of intent. It has also been prescribed that generally letters of intent can be extended only upto a period of five years after which the letters of intent will be treated as lapsed.

सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग

2378. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में कितने भारी उद्योग चलाये जा रहे हैं तथा उनमें से प्रत्येक में कितनी पूंजी का निवेश किया गया है, उनकी अलग-अलग वार्षिक खपत कितनी है तथा उनकी इस मांग को किस तरह से पूरा किया जाता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि जापान में भारी उद्योगों की 90 प्रतिशत आवश्यकता को मध्यम और लघु उद्योगों द्वारा पूरा किया जाता है तथा मध्यम दर्जे के उद्योग बदले में अपनी मांग को छोटे और लघु उद्योगों के द्वारा पूरा करते हैं जिसके फलस्वरूप उद्योग गांव के स्तर तक फैल गये हैं और इस तरह से गांव को शहरों में बदल दिया गया है, यदि हां, तो क्या भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके द्वारा इस प्रकार के मध्यम दर्जे, लघु उद्योग और भारी उद्योगों के सहायक उद्योगों के आधार पर ऐसे स्थानों पर उद्योगों को स्थापित किया जा सके, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) 31-3-1986 को 128 भारी उद्योगों में उनकी सकल परिसम्पत्ति के रूप में 51,080.23 करोड़ रुपये का पूंजी-निवेश किया गया है। उनकी अलग-अलग वार्षिक खपत और ऐसी खपत को पूरा करने की पद्धति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जापान के भारी उद्योगों की मध्यम और लघु उद्योगों द्वारा पूरी की जा रही मांग की सही प्रतिशतता ज्ञात नहीं है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के नाभिकीय क्षेत्र के आस-पास आर्थिक दृष्टि से सक्षम सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सदुपाय किये हैं, जिनके परिणामस्वरूप 31-3-1986 तक 1800 एकक स्थापित किये जा चुके हैं।

Consignment Agents of IPCL

2379. SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the norms laid down by the Indian Petro-chemicals Corporation